



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2015/वैशाख 15, 1937

No. 151]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2015/VAISAKHA 15, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 1 मई, 2015

सं. टीएमपी/5/2011-वीएसपीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/5/2011-वीएसपीएल

कोरम:

- (i). श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(अप्रैल 2015 के 28वें दिन पारित)

यह मामला विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) में बर्थ ईक्यू-8 और ईक्यू-9 में इसके द्वारा प्रहस्तित पोतों के लिए विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वीएसपीएल) के मौजूदा दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

- 2.1. वीएसपीएल का मौजूदा दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएमपी/5/2011-वीएसपीएल दिनांक 11 अक्टूबर 2011, जिसे 22 नवम्बर 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस आदेश ने दरमान की वैधता 31 मार्च 2014 तक निर्धारित की थी।
- 2.2. वीएसपीएल ने हारबर मोबाइल क्रेन के लिए निर्धारित प्रशुल्क की सीमा तक के लिए माननीय आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना उच्च न्यायालय में उक्त आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2011 को चुनौती दी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने वीएसपीएल को आगे आदेशों तक हारबर मोबाइल क्रेन के लिए इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रु० 36.70 प्रति टन की बजाय रु० 72.75 प्रति टन की पूर्व-संशोधित दर वसूल करने की अनुमति दे दी थी।
- 2.3. वीएसपीएल के मौजूदा दरमान की वैधता (हारबर मोबाइल क्रेन की दर के लिए वैधता के सिवाय जो न्यायाधीन है) कई अवसरों पर विस्तारित की गई थी; पिछला विस्तार आदेश दिनांक 2 जनवरी 2015 द्वारा 31 मार्च 2015 तक किया गया था।
3. वीएसपीएल द्वारा अपने पत्र दिनांक 10 मार्च 2014 द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव पर प्रासंगिक उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

4. संयुक्त सुनवाई, परामर्शी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, 7 अक्टूबर 2014 को आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में यथा निर्णीत, वीएसपीएल से हमारे पत्र दिनांक 16 अक्टूबर 2014 द्वारा अनुरोध किया गया था कि संयुक्त सुनवाई में उपयोक्ताओं में से एक उपयोक्ता, वीएसएए द्वारा किए गए लिखित निवेदन पर अपनी टिप्पणियां भेजे। हमारे पत्र दिनांक 16 अक्टूबर 2014 द्वारा वीएसपीएल और वीपीटी दोनों को अनुस्मरण करवाया गया था कि हमारे पत्र दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर अपने तत्संबंधी जवाब भेजें। वीपीटी को 31 अक्टूबर 2014 और 26 नवम्बर 2014 को अनुस्मारक जारी किए गए थे। वीएसपीएल ने अपने पत्र दिनांक 20 नवम्बर 2014 द्वारा अपना जवाब भेजा था। चूंकि वीपीटी हमारे पत्र दिनांक 17 दिसम्बर 2014 द्वारा कुछ बिन्दुओं पर जवाब भेजा था, इसलिए वीपीटी से हमारे पत्र दिनांक 16 जनवरी 2015 द्वारा अनुरोध किया गया था कि शेष बिन्दुओं पर अपना जवाब भेजे। वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 6 मार्च 2015 द्वारा अपना जवाब भेजा है। इस मामले की जांच की जा रही है और इस मामले को अंतिम रूप देने तथा संशोधित दरमान अधिसूचित करने में कुछ और समय लगेगा।

5.1. वीएसपीएल के मौजूदा दरमान की विस्तारित वैधता 31 मार्च 2015 को समाप्त हो चुकी है। उपर्युक्त पैरा 4 में दी गई स्थिति के मद्देनजर और यह स्वीकार करते हुए कि इस मामले पर अंतिम रूप से विचार करने में समय लगेगा, यह प्राधिकरण मौजूदा दरमान की वैधता (हारबर मोबाइल क्रेन की दर के लिए वैधता के सिवाय जोकि न्यायाधीन है) इसकी समाप्ति की तारीख से 30 सितम्बर 2015 तक अथवा संशोधित दरमानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

5.2. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष 1 अप्रैल 2014 के बाद की अवधि के लिए प्रकट होता है तो इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन—III/4/असा./143/2015(40)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st May 2015

No. TAMP/5/2011-VSPL.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of Vizag Seaport Private Limited as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/5/2011-VSPL

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 28th day of April 2015)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Vizag Seaport Private Limited (VSPL) for the vessels handled by it at berth Nos.EQ-8 and EQ-9 at the Visakhapatnam Port Trust (VPT).

2.1. The existing Scale of Rates (SOR) of VSPL was last approved by this Authority vide Order No.TAMP/5/2011-VSPL dated 11 October 2011 which was notified in the Gazette of India on 22 November 2011. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2014.

2.2. The VSPL has challenged the said Order dated 11 October 2011 in the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh and Telangana to the extent of the tariff fixed for the Harbour Mobile Crane. The Hon'ble High Court has permitted the VSPL to levy the pre-revised rate of ₹72.75 per tonne instead of ₹36.70 per tonne approved by this Authority for the Harbour Mobile Crane until further orders.

2.3. The validity of the existing SOR (except the validity for the rate of Harbour Mobile Crane which is subjudice), of the VSPL has been extended on couple of occasions; the last extension being till 31 March 2015 vide Order dated 2 January 2015.

3. The proposal filed by the VSPL vide its letter dated 10 March 2014 has been taken on consultation with relevant users/user associations.

4. Joint hearing, as part of the consultative process, was held on 7 October 2014. As decided at the joint hearing, VSPL was requested vide our letter dated 16 October 2014 to furnish its comments on the written submission made by one of the users, VSAA at the joint hearing. Both the VSPL and VPT were also reminded vide our letter dated 16 October 2014 to furnish their respective reply to the queries raised by us vide our letter dated 29 September 2014.

Reminders to VPT issued on 31 October 2014 and 26 November 2014. VSPL *vide* its letter dated 20 November 2014 has furnished its reply. Since the VPT had furnished reply only on a few points *vide* its letter dated 17 December 2014, the VPT was again requested *vide* our letter dated 16 January 2015 to furnish its reply to the remaining points. The VPT has *vide* its letter dated 6 March 2015 furnished its reply. The case is being examined and it will take some more time to finalise and notify the revised SOR.

5.1. The extended validity of the existing SOR of VSPL has expired on 31 March 2015. In view of the position brought out in para 4 above and recognising that it will take some more time to finalise the case, this Authority extends the validity of the existing SOR, (except the validity for the rate of Harbour Mobile Crane which is subjudice), from the date of its expiry till 30 September 2015 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

5.2. If any surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April 2014, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Exty/143/2015(40)]